

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वांतियर, कैम्प हागर १०० प्र० १

निग० प्रक० क्र०

R 1388-I-17 अग 2017

81

लकडू उर्फ लखनलाल तनयनन्नेलाल यादव आयु 55 वर्ष

नि ग्राम गेवलाई, तहसील बकस्वाहा जि.छतरपुर म.प्र. ---- निगरानीकर्ता

बनाम

राजरानी पत्नी अछैलाल यादव आयु वर्ष

नि० गेवलाई, तहसील बकस्वाहा जि.छतरपुर म. प्र. --- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भ.रा.सं.

योग्य अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, बकस्वाहा के रा.प्रक.क्र. 43/अ/2/203-14 मे पारित

आदेश दिनांक 16-03-2017 से दुखित होकर यह निगरानी पेश की जा रही है।

Handwritten notes: 21/1/17, 2/1/17, 5/1/17, 25/4

महोदय,

प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न विनय है:-

१११ यह कि भूमि खेरा नंबर 246/1 रकबा 0.101 है० आबादी भूमि ग्राम गेवलाई, तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर मे स्थित है जो निगरानी कर्ता की पत्रिक स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थी अपना मवेशी बांधने हेतु बैड़ा एवं झोटा रकने हेतु टपरा बनाकर के काबिज बना आ रहा है।

११२ यह कि भूमि खेरा नंबर 245, 246/2 रकबा 0.174 है० स्थित ग्राम गेवलाई तहसील बकस्वाहा जिला छतरपुर मे है जो राजस्व रिकार्ड मे गैरनिगरानीकर्ता के नाम पर दर्ज है। गैरनिगरानीकर्ता के आवेदन पर भूमि खेरानंबर 245, 246/2 जुज रकबा 0.174 है० का सीमांकन रा.निरो.सं. बकस्वाहा द्वारा किया गया जिस पर निगरानीकर्ता के द्वारा आपत्ति पेश योग्य न्यायालय मे की गयी थी जिसे निरस्त कर यह आयोग्य आदेश पारित किया गया है जिसे दुखित होकर यह निगरानी निम्न आधारों एवं तथ्यों पर पेश की जा रही है।

:- निगरानी के आधार एवं तथ्य -:

११३ यह कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय बकस्वाहा के समक्ष

Handwritten signature

२१


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1388-एक/2017

जिला छतरपुर

लखवू विरूद्ध राजरानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार बकस्वाहा के प्रकरण क्रमांक 43/अ-12/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 16-03-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 	<p style="text-align: right;">  (आर.क. प्रसाद) सतस्य </p> <p style="text-align: right; font-size: 2em;">3.1.19.</p>